Election Commission of India

22

15 OCT 2012

NAME OF THE NEWSPAPER राष्ट्रीय सहारा DATE:

कुछ कहते हैं नतीजे

उपचुनाव के परिणाम व्यापक जनमत को परखने का आधार तो नहीं होते, लेकिन इन्हें राजनीतिक रुझान का सीमित संकेतक जरूर माना जाता है। इस लिहाज से उत्तराखंड की टिहरी और पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे विश्लेषण योग्य हैं। खासकर तब जबकि ये दोनों सीटें आम चुनाव में कांग्रेस ने जीती थीं। यकीनी तौर पर चुनाव नतीजे कांग्रेस की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। पार्टी ने जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय बहुगुणा द्वारा खाली की गई टिहरी सीट को भाजपा के हाथों गंवा दिया, वहीं राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पश्चिम बंगाल की प्रणब मुखर्जी की छोड़ी सीट जंगीपुर पर वह मामूली अंतर से काबिज रह सकी। पहले बात उत्तराखंड की टिहरी सीट की, यहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को इस उम्मीद से उम्मीदवार बनाया था कि वे अपनी राजनीतिक विरासत और युवा आकर्षण की बदौलत जीतने में सफल रहेंगे। लेकिन भाजपा उम्मीदवार माला राज लक्ष्मी शाह ने उन्हें बीस हजार से अधिक मतों से पराजित कर कांग्रेसी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। यह पराजय इस लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को सत्ता संभाले अभी तकरीबन छह माह ही हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुत्र की इस हार को कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहां भाजपा की उम्मीदवार रहीं माला राज लक्ष्मी शाह को भी अपने श्वसुर की राजनीतिक विरासत का सहारा था, लेकिन व्यापक तौर पर उनकी जीत कांग्रेस के लिए करारा झटका और भाजपा का मनोबल बढ़ाने वाली है। जहां तक पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट का प्रश्न है तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी के समक्ष ममता बनर्जी द्वारा अपना प्रत्याशी न उतारने के बाद उनकी राह बहुत हद तक निरापद मानी जा रही थी। लेकिन मतगणना के दौरान कमजोर समझे जा रहे वाममोर्चे के प्रत्याशी ने अभिजीत मुखर्जी से जमकर होड़ लगाई। अंततः अभिजीत महज 2536 मतों के अंतर से विजयी रहे। यदि प्रणब दा की विरासत का सहारा न होता और ममता का प्रत्याशी मैदान में होता तो ज्यादा संभावना थी कि यह सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाती। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह जीत भी खतरे की घंटी है। अलबत्ता जंगीपुर की हार जितनी नजदीकी रही, उससे वाममोर्चे का मनोबल जरूर बढ़ेगा। इसके आधार पर ममता बनर्जी भी यूपीए से अलग होने के फैसले को तर्कसंगत ठहरा सकेंगी। दरअसल, यूपीए-2 सरकार के इस उत्तरार्ध काल में यूपी सहित पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों से लेकर 2014 के पहले तक जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, उनका आकलन अगले आम चुनाव के दृष्टिगत किया जाएगा। चुनावी रुझान को परखने का अगला पैमाना गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा नतीजे होंगे।